जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 14 संख्याः 333 प्रभात चूरू, मंगलवार 4 अप्रेल, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली स्टॉर्क की एकमात्र प्रजाति है वुड स्टॉर्क। लगभग पचास सालों तक विलुप्ति के कगार पर रहने के बाद सारस की यह प्रजाति अब एन्डेन्जर्ड स्पीशीज़ लिस्ट से बाहर हो सकती है। गौरतलब है कि, अमेरिका में चलाए जा रहे संरक्षण कार्यक्रम का नवीनतम लाभार्थी वुड स्टॉर्क ही है, इसे 1984 में एन्डेन्जर्ड स्पीशीज़ एक्ट के दायरे में लिया गया था। उस समय इसके घोंसला बनाने वाले जोड़ों की संख्या 20,000 से घटकर मात्र 5000 रह गई थी। ये पक्षी साउथ फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स क्षेत्र और बिग सायप्रस इकोसिस्टम में घर बनाते हैं। रिकवरी कार्यक्रम का लक्ष्य था, उन इकोसिस्टम्स की रक्षा करना व उन्हें पूर्व की स्थिति में लाना, जिन्हें साढ़े चार फुट लम्बे ये वुड स्टॉर्क अपना घर कहते हैं। आज वुड स्टॉर्क के प्रजनन करने वाले जोड़ों की संख्या दस हजार हो गई है, यही नहीं, इनकी रेंज का विस्तार भी हुआ है। दलदली इलाकों और नदियों में मछली, मेंढक तथा क्रस्टेशिअन्स (कड़े खोल वाले जानवर) का शिकार करने वाले इन पक्षियों की बस्तियां 29 से बढ़कर 99 हो गई हैं। फिश एण्ड वाइल्डलाइफ विभाग ने बताया कि, लम्बी टांगों वाले ये पक्षी अपने नए आवासीय क्षेत्रों से अनुकूलन कर रहे हैं और तटवर्ती सॉल्ट मार्श क्षेत्र में उत्तर की तरफ, पुराने चावल के खेतों में, जंगल के वैटलैण्ड्स और मानव निर्मित वैट लैण्ड्स में घर बनाने लगे हैं। एण्डीज़ पर्वत श्रृंखला के पूर्व की तरफ लगभग सम्पूर्ण साउथ अमेरिकन महाद्वीप में फैली इनकी रेंज के कारण इन्टरनैशनल यूनियन फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में इसे ''लीस्ट कन्सर्न'' वर्ग में रखा गया है। फिश एण्ड वाइल्डलाइफ, एण्ड पार्क्स विभाग की सह सचिव शैनन एस्टीनोज़ ने कहा कि, आवास संरक्षण की वजह से ही इन पक्षियों की संख्या बढ़ी है।

राहुल को कुछ समय और मोदी कांग्रेस का नेतृत्व प्रदान करने देना चाहते हैं

अगर राहुल से नेतृत्व प्रदान करने का अधिकार छिन जाता है तो, यह जिम्मेवारी निभाने के लिये प्रियंका गांधी को आगे आना पड़ेगा

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। राहुल गांधी को अब लम्बे समय तक अदालतों के चक्कर लगाने होंगे तथा गुजरात की अदालतों से अपनी दोष-सिद्धि के फैसले को पलटवाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें जमानत मिल गई है तथा इसलिये उन्हें, कम से कम फिलहाल तो, जेल नहीं जाना पड़ेगा।

राजनैतिक पंडितों का कहना है कि राहुल गांधी का चुनाव लड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि गुजरात की अदालतों की कानूनी प्रक्रिया लम्बे समय तक चलती, बल्कि घिसटती रहेगी।

गुजरात के सत्र-न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है तथा अदालत उनकी दोष-सिद्धि को उलटने के लिये दायर की गई याचिका की सुनवाई 13 अप्रैल से करेगी।

राहुल गांधी का अदालत में उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा क्योंकि अपील का काम उनके वकील सँभालेंगे।

आज अपील दायर करने के लिये भी उन्हें अदालत में उपस्थित होने की जरुरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहाँ भीड़ इकट्ठी करने तथा राहुल गांधी के प्रति जनता की सद्भावना का संदेश भेजने का निर्णय लिया था।

- इस प्रकार का घटनाक्रम, भाजपा के पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी तो कोर्ट केसों में फंसे होने के कारण, अपनी व्यस्तता के कारण कांग्रेस को पूर्ण एकाग्रता व समय नहीं दे पा रहे।
- पर, प्रियंका गांधी के समक्ष ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी। यह भांपते हुए, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता गण, अब प्रियंका गांधी की ओर मुड़ने लगे हैं।
- इस झुकाव को आगे बढ़ने देने का मौका नहीं देने के लिये, राहुल गांधी ने सूरत के न्यायालय में स्वयं उपस्थित होने का निर्णय लिया, हालांकि, वहां न्यायालय में उनकी स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी।
- कांग्रेस ने, सूरत में राहुल की उपस्थिति को भारी महत्व देते हुए भारी संख्या में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को न्यायालय प्रांगण में भेजा तथा कांग्रेस के तीनों मु. मंत्रियों को भी न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी। प्रियंका गांधी इस मौके पर सारे समय मौजूद रहीं।
- पर जानकार लोगों का यह भी मानना है कि, इस हालात में राहुल गांधी का चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि, राहुल को गुजरात के न्यायालयों से जल्दी कोई भी रिलीफ मिलने की आशा नहीं है तथा मुकदमा लम्बे समय तक खिंच सकता है।

लेकिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि राहुल गांधी यह संदेश भी भेजना चाहते थे कि वे अब भी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा हैं।

कांग्रेस के तीनों मुख्यमंत्रियों- राजस्थान के अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल तथा हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू को सूरत में उपस्थित होने को कहा गया था। गुजरात के पार्टी नेताओं को प्रियंका गांधी के साथ-साथ सूरत जाने के लिये कहा गया था।

लोकसभा और राज्यसभा के कांग्रेस सांसदों से कहा गया था कि वे संसद भवन में एकत्रित होने के लिए कह दिया गया था ताकि राहुल गांधी के प्रति एकजुटता दर्शायी जा सके।

पार्टी के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर नरेन्द्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।
कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
फ्री सुनाई की जाँच
TRIAL OF HEARING AID
CALL FOR APPOINTMENT
+91 94602 07080
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
www.perfecthearingsolutions.com

'छह साल पहले दिए आदेश की पालना करो वरना हाजिर हों स्वास्थ्य सचिव'

जयपुर, 3 अप्रैल (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चयनित वेतनमान से जुड़े मामले में छह साल पहले दिए आदेश की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हाईकोर्ट ने 25 मई, 2017 में आदेश जारी कर चार माह में पालना के लिए कहा था,

- हाई कोर्ट ने 25 मई 2017 को चिकित्सा विभाग के एक कर्मचारी को नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था, पर आदेश की अब तक पालना नहीं हुई है। इसीलिए हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को तलब किया है।

लेकिन छह साल बीतने के बाद भी अब तक आदेश की पालना नहीं हुई है। ऐसे में यदि अब भी आदेश की पालना नहीं हो तो पांच अप्रैल को स्वास्थ्य सचिव व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बताएं कि छह साल बीतने के बाद भी अब तक आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश बी.एन. शर्मा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता चिकित्सा विभाग में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। उसे चयनित वेतनमान का लाभ नियुक्ति तिथि से नहीं दिया गया और चयनित वेतनमान निचले पे-स्केल से दिया गया। इसे चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने 25 मई 2017 को विभाग को आदेश दिए थे कि चार माह में याचिकाकर्ता को प्रथम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सपा की ''दलित मैत्री'' नीति से मायावती विचलित हुईं

अखिलेश ने पहले तो कांशीराम के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया और अब डॉ. अम्बेडकर के जन्मदिन पर और भारी आयोजन करने की घोषणा की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी ताकतवर रही बहुजन समाज पार्टी, जो राष्ट्रीय राजनीति में ऐतिहासिक भूमिका निभाने की आकांक्षी थी, अब महत्वहीन होती जा रही है तथा चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती अपनी पार्टी को अकेली ही खींचती तथा अपने दलित जनाधार को अपने पास बनाये रखने के लिये हाथ-पैर मारती दिखाई दे रही हैं।

समाजवादी पार्टी ने हाल ही में बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयन्ती मनाई थी तथा उसी वक्त घोषणा कर दी थी कि वह (सपा) 14 अप्रैल को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनायेगी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दलितों को आकर्षित करने के नियोजित प्रयासों को लेकर खीजी हुई मायावती ने कल लखनऊ में आयोजित बसपा के प्रान्तीय पदाधिकारियों तथा जिला इकाई अध्यक्षों की मीटिंग में कहा कि सपा ने ''मान्यवर कांशीराम जी के नाम का फायदा उठाने का राजनैतिक स्टंट शुरु कर दिया है, जबकि इसका लम्बा इतिहास दलितों के प्रति राजनैतिक एवं जातीय शत्रुता का रहा है।''

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि सपा कांशीराम, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर तथा अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रति कृतघ्न रही है तथा उसके इसी रूख के कारण, 1995 की ''गैस्ट हाउस'' घटना हुई थी तथा सपा के साथ हमारा गठबंधन समाप्त हो गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- मायावती ने कहा, सपा का इतिहास, दलितों से शत्रुता व दमन की कार्यवाहियों से भरा हुआ है और दलितों से मैत्री केवल एक राजनीतिक स्टंट है सपा का।
- यह सच है कि, यादवों पर दलितों के दमन व अत्याचार का आरोप किसी हद तक सच है, पर, अब वर्तमान राजनीतिक माहौल में उस आरोप को दोहराना, भाजपा विरोधी एकता को कमजोर करना है।

'इंग्लिश मीडियम में पढ़े अभ्यर्थी ही पात्र क्यों?'

जयपुर, 3 अप्रैल (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक संविदा भर्ती-2023 में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र मानने पर शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मयंक कुमार शर्मा की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राजस्थान हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक संविदा भर्ती 2023, में सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में पढ़े अभ्यर्थी को ही पात्र मानने पर शिक्षा सचिव, पंचायती राज सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है।

सिद्धू को फिलहाल पंजाब से बाहर ही रखेगी कांग्रेस

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। 1998 के रोड रेज केस में, 10 महीने की कैद की सजा काटने के बाद, क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की पटियाला जेल से रिहा हो गये लेकिन उन्हें उनके गृह राज्य पंजाब में कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना नहीं है।

उनकी कैद की अवधि के दौरान, पंजाब में कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है।

युवा नेता अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग पंजाब पी.सी.सी. के अध्यक्ष नियुक्त कर दिये गये हैं तथा प्रताप सिंह बाजवा के पास राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद का दायित्व है। राज्य में पार्टी जिस तरह से चल रही है, उससे कांग्रेस नेतृत्व संतुष्ट प्रतीत हो रही है। इस बीच, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि सिद्धू ने जेल में अपनी मुलाकातों के चलते, पिछले 10 महीनों में अपनी कोई अच्छी छवि प्रस्तुत की हो। जेल में उनसे मुलाकात करने वाले लोगों में मनप्रीत बादल शामिल हैं, जो कई कांग्रेस नेताओं को साथ लेकर कुछ महीने पहले भाजपा में पहुँच गये हैं। गत वर्ष पी.सी.सी. अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान, सिद्धू ने कुछ विवादों को भी जन्म दे दिया था, जिनके परिणामस्वरूप पार्टी कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये थे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ''इसलिये ऐसी संभावना नहीं है कि पार्टी इसी समय सिद्धू को पंजाब में कोई बड़ी भूमिका दे दे।''

महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनकी रिहाई पर जेल से बाहर उनका स्वागत करने के लिये राज्य के बड़े कांग्रेस नेता उपस्थित नहीं थे। लेकिन जहाँ तक सिद्धू का प्रश्न है, अपनी रिहाई के बाद वे विवादों से दूर हैं। हाँ, उन्होंने केन्द्र सरकार तथा राज्य की आप सरकार की कड़ी आलोचना जरूर की है।

सिद्धू की अपनी ताकत एवं मजबूत पक्ष भी है। वे फायर ब्रान्ड नेता तथा प्रखरवक्ता है। वे सुपरिचित एवं लोकप्रिय हस्ती है तथा अपने राजनैतिक विरोधियों से टक्कर लेने के मामले में निडर हैं।

इसलिये ऐसा संभव है कि कर्नाटक के सन्निकट चुनावों में उनसे प्रचार करने के लिये कहा जाये तथा उसके बाद, उन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा तेलंगाना में भी प्रचार का दायित्व सौंपा जाये। इस प्रकार निकट भविष्य में सिद्धू को पंजाब से बाहर रखे जाने की संभावना है।

- सिद्धू के दस महीने के जेल प्रवास में कांग्रेस ने पंजाब में नये पी.सी.सी. अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह राजा वारिंग तथा नये विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में टीम विकसित कर ली है तथा कांग्रेस इस टीम को ''डिस्टर्ब'' नहीं करना चाहेगी।
- कांग्रेस सिद्धू को पहले कर्नाटक व बाद में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में जरूर उपयोग करेगी।

अचानक सऊदी अरब ने अपना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन घटाने की घोषणा की

अन्य ओपेक देशों ने भी इस मामले में सऊदी अरब के साथ खड़े होते हुए अपना ऑयल प्रोडक्शन घटाया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 अप्रैल। सऊदी अरब द्वारा तेल के उत्पादन मे अचानक से कटौती किए जाने के निर्णय से दुनिया अचानक से एक गंभीर संकट में आ गई है। सऊदी अरब के इस निर्णय के साथ ही ऑर्गनाइजेशन ऑफ पैट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज़ (ओ.पी.ई.सी.) व उसके अन्य सदस्य देशों ने भी अपने-अपने उत्पादन में इसी अनुरूप कमी करने की घोषणा की है।

तेल के वैश्विक उत्पादन में कुल कमी का आकलन प्रयोगात्मक रूप में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का किया जा रहा है, जो कि वैश्विक मांग का 2 प्रतिशत है। तेल की कीमतें आज वैश्विक बाजारों में करीब 5.5 प्रतिशत तक बढ़ीं।

ऑयल मार्केट विशेषज्ञों को आशंका है कि इस वर्ष के अन्त तक तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। इसके मायने भारत के साथ ही दुनिया के लिए बेचैन करने वाले हो सकते हैं। इससे वैश्विक बाजारों में स्थायित्व की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। केन्द्रीय बैंक का विकार अब यह है कि पहले ब्याज दरों में वृद्धि के काम को कभी-कभी रोका गया, ताकि आर्थिक रिकवरी अवरूद्ध ना हो। तथापि, तेल की कीमत वृद्धि और सामान्य वस्तुओं की कीमत पर पड़नें वाले इसके असर की आशंका इतनी अधिक है, कि केन्द्रीय बैंकों को अपने नरम रूख पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

तथापि, इन सतही घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच बढ़ते रूखे संबंध हैं।

तेल उत्पादन में कटौती के इस वक्त लिए गए निर्णय की अमेरिका ने यह कहते हुए कड़ी आलोचना की है कि तेल की कीमतों में अपरिहार्य रूप से हुई वृद्धि से रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। इससे पहले, जब सऊदी अरब ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में अपने तेल उत्पादन में थोड़ी कटौती की थी तब अमेरिका ने इसी भांति उस निर्णय का विरोध करते हुए सऊदी अरब को धमकी दी थी कि वह इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।

अब अमेरिकी प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि सऊदी अरब के लिए हथियारों और रणनीतिक सिस्अम्स की बिक्री में अच्छी-खासी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- रूस भी इस घटनाक्रम से काफी प्रसन्न है तथा उसने भी अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में उतनी ही कटौती करने की घोषणा की, जितना प्रोडक्शन सऊदी अरब ने कम किया है।
- रूस खुश इसलिये है कि, अब उसके क्रूड ऑयल के दाम अपने आप बढ़ेंगे और अपनी क्रूड ऑयल की बिक्री से बढ़े रैवेन्यु के कारण, वो अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों को आसानी से झेल पायेगा तथा यूक्रेन की लड़ाई को आसानी से लंबे समय तक लड़ पायेगा।
- गत अक्टूबर में भी सऊदी अरब ने प्रोडक्शन घटाने की बात कही थी, पर, अमेरिका के आर्थिक व राजनीतिक दबाव के कारण, पीछे हट गया था।
- पर, अब चीन द्वारा सऊदी व ईरान के बीच ''दोस्ती'' करवा देने से, व चीन व रूस के सर्वविदित संबंधों के साये में सऊदी अरब काफी मजबूती महसूस कर रहा है तथा अमेरिका के दबाव को नकार रहा है।

राजेन्द्र राठौड़ दिल्ली में प्र.मंत्री मोदी से मिले

जयपुर, 3 अप्रेल (का.सं.)। भाजपा के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सोमवार को दिल्ली गए। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी के साथ राठौड़ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से भी मुलाकात की।

राठौड़ ने लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, स्पीकर ओम बिड़ला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व अन्य प्रमुख केन्द्रीय नेताओं से भी मुलाकात की।